घोटाले छिपाने के लिए मिशेल का इस्तेमाल कर रही भाजपाः कांग्रेस

● कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुद की चोरी छिपाने के लिए शोर मचाने का लगाया आरोप

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुद की चोरी छिपाने के लिए शोर मचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह इस मामले में गिरफ्तार क्रिश्चयन मिशेल का इस्तेमाल खुद के घोटाले छिपाने के लिए कर रहे हैं।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने रविवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घोटाले से बचने के लिए मोदी सरकार षड़यंत्रकारी पटकथा लिखने में व्यस्त हैं और इसके जरिये वह गड़बड़झालों तथा घोटालों को छिपाने में जुटी हुई है। श्री मोदी पर सीधे तौर से इस घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे इस पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता साबित होती है। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार इस घोटाले में शामिल नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए कि जिस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने काली सूची में डाल दिया था तो इस कंपनी को 'मेक इन इंडिया' का हिस्सा क्यों बनाया गया और किस आधार पर विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अगस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर बनाने की इजाजत दी गयी। प्रवक्ता ने सवाल किया कि मोदी को यह भी बताना चाहिए कि जो कंपनी काली सूची में डाली गयी थी उसको किस आधार पर नौसेना के लिए सौ हेलीकॉप्टरों की बोली लगाने की अनुमति दी गयी। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ किए गए सभी मुकदमे कैसे हार गई और यदि हार भी हुई है तो मुकदमों की अपील क्यों नहीं की गयी?

पांच राज्यों में चुनाव लड़ेगी 'आप'

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की राष्ट्रीय परिषद ने अगले साल लोकसभा चुनाव और इसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। शनिवार को हुई परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता पंकज गुप्ता ने बताया, 'अगले साल लोकसभा चुनाव और उसके कुछ महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इस परिषद की कार्य अवधि को एक साल और बढ़ाया जाए।' 'आप' दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही वह पंजाब, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 'आप' की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसकी जानकारी दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने दी। दिल्ली समेत 5 राज्यों में लोकसभा की सभी सीटों पर 'आप' के लड़ने की घोषणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन की संभावना कम हो गई है।

न्यूज डायरी

दिल्ली की सीमाओं पर 12 'स्वागत द्वार' बनाएगी सरकार

नई दिल्ली। आप सरकार ने अगले वर्ष तक राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में प्रवेश के 12 बिन्दुओं पर 'स्वागत द्वार' बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। सिसोदिया ने बताया कि 'स्वागत द्वार' नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, कड़कड़डूमा, बहादुरगढ़, बादली, गुरुग्राम, कुंडली और गाजीपुर में बनेंगे। इसका लक्ष्य दिल्ली में प्रवेश करने वालों को आकर्षक और खुशनुमा दृश्य प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 127 छोटे प्रवेश बिन्दु हैं। मैंने 12 मुख्य सीमा प्रवेश बिन्दुओं पर 'स्वागत द्वार' बनाने के डीटीटीडीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन द्वारों के ऊपर 'दिल्ली में स्वागत है' लिखा होगा।

नेशनल काउंसिल की मीटिंग में अलका लांबा को न्योता नहीं

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) में अलका लांबा को लेकर मचा घमासान अभी शांत होता नहीं दिख रहा। खबर है कि शनिवार को हुई आप की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा को नहीं बुलाया गया। जबकि इससे पहले हुई नेशनल काउंसिल की सभी मीटिंग्स में उन्हें हिस्सा बनाया गया था। लांबा के एक करीबी सूत्र ने बताया कि अलका ने शनिवार सुबह तक के अपने सभी एसएमएस और ईमेल्स चेक किए, उन्हें लगा कि शायद मेसेज उनसे मिस हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद 10 बजे करीब अलका ने सोशल मीडिया पर 'हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली' गाना शेयर किया। माना जा रहा है कि अलका ने यहां इशारों-इशारों में आप नेतृत्व से सवाल किया था। बता दें कि अलका को यह जानकारी भी मिली की कार्यक्रम में मौजूद अटेंडेंस शीट पर बाकी सभी के साथ उनका भी नाम था। शीट पर सबने साइन भी किए, लेकिन अलका नहीं गई थीं इसलिए उनकी जगह खाली रही।

ब्लूटूथ से नकल करने की कोशिश, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की मल्टी ट्रास्किंग स्टॉफ भर्ती परीक्षा में नकल करने की कोशिश करने वाले एक परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विक्रम के रूप में हुई है। वह रोहतक का रहने वाला है। इससे पहले शुक्रवार को भी पुलिस ने दो परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार एएसआई रामबीर सिंह शाहदरा जिले के पुलिस लाइन में तैनात हैं। इस समय उनकी ड्यूटी सोनिया विहार थाना इलाके के बजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में चल रही मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ की भर्ती परीक्षा में लगी है।

फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंची दिल्ली की वायु गुणवत्ता

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषकों का छितराव धीमा होने से रविवार को वायु गुणवत्ता गिरकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 412 दर्ज किया गया जो 'गंभीर श्रेणी' में आता है जबकि केंद्र द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली (सफर) ने एक्यूआई 388 दर्ज किया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। सफर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से दिन-रात मौसमी प्रवृत्ति पर नजर रखी गई। उसने कहा, ''रात के समय धीमी हवा और ठंड प्रदूषण स्तर बढ़ा रही है। कई जगहों पर एक्यूआई कुछ घंटों के लिए 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया जबकि दिन के दौरान हवा थोड़ी-सी तेज चल रही है और तापमान बढ़ रहा है जिससे प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' रहा।' वायु गुणवत्ता 10 दिनों में चौथी बार रविवार को सुबह 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, 27 इलाकों में प्रदूषण 'गंभीर' स्तर पर दर्ज किया गया जबकि आठ इलाकों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई। एनसीआर, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' दर्ज की गई जबकि फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई। सीपीसीबी ने बताया कि दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 339 और पीएम 10 का स्तर 506 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को 450 के एक्यूआई के साथ साल में दूसरा सबसे अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया। सोमवार और मंगलवार को भी वायु गुणवत्ता 'गंभीर' रही। बुधवार को मामूली सुधार देखा गया। गुरुवार को आबोहवा फिर से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। सफर ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब है जिसमें दिन में तेज हवा चलने से स्थिति में मामूली सुधार हो सकता है लेकिन कल तक वायु गुणवत्ता खराब होने का अनुमान है। अगले कम से कम दो दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। उसने कहा, 'वायु गुणवत्ता सूचकांक अगले तीन दिनों के लिए 360-380 के बीच रहेगा जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।'

राहुल गांधी में उत्कृष्ट प्रधानमंत्री बनने की सभी खूबियां: थरूर

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी में एक 'उत्कृष्ट' प्रधानमंत्री बनने की सभी खूबियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर 2019 के चुनाव के बाद पार्टी और सहयोगी दल संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। थरूर ने कहा कि हाल में सम्पन्न विधानसभा चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अभी भी पूरे देश में उपस्थिति रखने वाली एकमात्र राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए 'स्वभाविक आधार' होगी। उन्होंने एक साक्षात्कार में समाचार एजेंसी से कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, जिसका मतलब है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो वह प्रधानमंत्री होंगे। अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार में है तो जाहिर है कि उम्मीदवार पर सहमति बनाने के लिए गठबंधन के अन्य दलों के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह 'संयुक्त फैसला' होगा और चुनाव नतीजों के बाद ही इस पर चर्चा होने की संभावना है। थरूर ने कहा कि निजी स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई चर्चाएं हुई, मेरे हिसाब से यह स्पष्ट है कि राहुल के पास देश का उत्कृष्ट प्रधानमंत्री बनने की सभी खूबियां हैं। 62 वर्षीय नेता ने कहा कि गांधी के नेतृत्व की समावेशी शैली, राजनीतिक रूप से विभाजित जन तक पहुंचने की इच्छा, समाज के पीड़ित तबकों के प्रति संवेदनाएं, देश के अनेकवादी ताने बाने को लेकर प्रतिबद्धता के साथ विनम्रता और उल्लेखनीय जागरूकता से साफ है कि वह इस पद की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं।

पार्किंग परियोजना दो वर्ष में पूरी करने का मांगा आश्वासन

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके के गांधी मैदान में पार्किंग का निर्माण कार्य सितंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाए। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने अग्निशमन विभाग, दिल्ली शहरी कला आयोग, धरोहर सरंक्षण समिति और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को 445 करोड़ रुपये की इस बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना के लिये 31 जनवरी 2019 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के लिये कहा है।

अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को नगर निगम की ओर से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) लेने के लिये दाखिल आवेदन पर तत्काल विचार करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को उसका फैसला निगम को जनवरी के अंत तक बताने के लिये कहा है। अदालत ने जोर दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र और पर्यावरण मंजूरी समयसीमा के भीतर प्रदान की जाए ताकि सितंबर 2020 तक परियोजना पूरी की जा सके। चांदनी चौक मेट्रो से लगी गांधी मैदान पार्किंग में फिलहाल 650 कारें ही खड़ी हो सकती हैं। नगर निगम ने इससे पहले अदालत को बताया था कि नई परियोजना के तहत इस पार्किंग को छह स्तरीय बनाया जाएगा, जिसमें तीन भूमिगत स्तर की पार्किंग भी शामिल है। एक तल का प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये किया जाएगा। इससे पार्किंग में 2500 कारें खड़ी हो सकेंगी।

यमुना नदी में कई गुना बढ़ा भारी धातु प्रदूषण

● एनजीटी द्वारा गठित निगरानी समिति ने निकाला निष्कर्ष
● प्रतिबंधित सामग्री से बनी मूर्तियों का विसर्जन है जिम्मेदार

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। यमुना की स्वच्छता का काम देख रही एक निगरानी समिति ने कहा है कि सिंथेटिक सामग्री से बनी और घातक पेंट से रंगी मूर्तियों के विसर्जन से यमुना में भारी धातु सांद्रण कई गुना बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने समिति को अवगत कराया कि गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन और छठ पूजा के दौरान होने वाली धार्मिक गतिविधियों ने नदी को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। समिति ने कहा कि 'यह अस्वीकार्य और खतरनाक' है। निगरानी समिति ने कहा है कि यमुना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है और न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह सुनिश्चित किए जाने तक इसके पुनरुद्धार की संभावना नहीं है क्योंकि असल में इसका प्रवाह ठहर गया है और कई जगहों पर यह साल में नौ महीने सूखी रहती है। समिति ने सुझाव दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित निगरानी समिति ने उल्लेख किया कि सिंथेटिक सामग्री से बनी और घातक पेंट से रंगी मूर्तियों के विसर्जन से नदी में भारी धातु सांद्रण बढ़ गया है। सीपीसीबी ने कहा कि नदी में मूर्ति विसर्जन के बाद क्रोमियम का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय की गई सीमा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से 11 गुना बढ़ गया। वहीं, लौह सांद्रण तय सीमा 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से 71 गुना और निकल का स्तर 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर से एक गुना तथा सीसा का स्तर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से दोगुना बढ़ गया। निगरानी समिति ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर मूर्ति विसर्जन के बाद नदी के पानी में 'प्रदूषक तत्वों का अस्वीकार्य स्तर% देखा गया।

इरविन कॉलेज के पास मिली महिला की जली लाश

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इरविन कॉलेज के बाहर फुटपाथ पर एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि वह जली हालत में था। महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि वह बेघर थीं। शायद, इधर-उधर घूमते हुए लोगों से पैसे मांगकर अपना जीवन चला रही थीं। पुलिस का यह भी कहना है कि उनकी मौत का कारण भूखे रहना नहीं था, क्योंकि जहां उनका शव मिला, वहां रोटी के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। नई दिल्ली जिले के डीसीपी मधुर वर्मा ने बताया कि महिला के शव को आरएमएल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि महिला को जलाकर मरा गया है।

कांग्रेस क्रिश्चन मिशेल का बचाव कर रही: भाजपा

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलिये क्रिश्चन मिशेल का बचाव कर रही है। भगवा पार्टी ने यह भी पूछा कि वह (कांग्रेस) मामले की जांच से भयभीत क्यों है। सत्तारूढ़ दल ने इस मुद्दे को कथित तौर पर राजनीतिक रंग देने को लेकर कांग्रेस की निंदा भी की और पूछा कि भ्रष्टाचार को लेकर जब कभी कोई विदेशी पकड़ा जाता है, तब गांधी-नेहरू परिवार के किसी सदस्य का नाम क्यों सामने आता है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद से कांग्रेस घबराई हुई है और उसका डर जाहिर है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस जांच से क्यों भयभीत है। विपक्षी पार्टी को कानून को अपना काम करने की इजाजत देनी चाहिए और मामले में भ्रष्टाचार की सच्चाई उजागर होनी चाहिए। उन्होंने पूछा, ''मैं एक मुनासिब सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 30-32 साल में जब कभी किसी विदेशी नागरिक का नाम भारत में भ्रष्टाचार के मामले में आया है, चाहे वह एंडरसन, ओतावियो क्वात्रोची, गुइडो हाश्के या क्रिश्चन मिशेल क्यों ना हो...वे गांधी परिवार के किसी सदस्य से क्यों जुड़े होते हैं। त्रिवेदी ने कहा कि सवाल यह है कि क्या अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश खुद संप्रग सरकार ने दिया था। अगस्ता वेस्टलैंड को काली सूची से हटाने और उसे नौसेना के लिए हेलीकॉप्टरों की निविदा में शामिल होने की इजाजत देने के कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इन कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले वायुयानों की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठता है बल्कि सौदों में भ्रष्टाचार पर सवाल है। त्रिवेदी ने बोफोर्स तोपों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे अच्छी गुणवत्ता के निकले और इसका यह मतलब नहीं है उनकी खरीद में हुए समूचे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया जा सकता है।

नए साल पर हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं!

नई दिल्ली। नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में वाहन चलाने व ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से दिल्ली पुलिस सख्ती से निपटेगी। पुलिस के 7500 जवान 31 दिसंबर को दिल्ली के 400 जगहों पर तैनात रहेंगे। इनमें से पांच हजार जवान दिल्ली में नियमित रूप से तैनात रहते हैं, जबकि ढाई हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। जवानों को स्थानीय पुलिस व पीसीआर से भी मदद मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि कनॉट प्लेस और खान मार्केट में 25-25 जवानों की 20 टीम तैनात की जाएंगी।

अधिकार न होने के कारण नौकरी देने में असमर्थ रही आप सरकार

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली के इतिहास में 2018 'ऐतिहासिक वर्ष' के तौर पर याद किया जाएगा क्योंकि इस वर्ष ही उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित सरकार को प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया लेकिन विवशता के चलते नौकरियों का सृजन नहीं कर पाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने समाचार एजेंसी से कहा कि दिल्ली को 1993 में विधानसभा मिली थी लेकिन 2018 में शासन एवं लोकतंत्र के संदर्भ में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय के चार जुलाई के आदेश के बाद आप सरकार और उपराज्यपाल के कार्यालय के बीच पहले की तुलना में 2018 में कम रस्साकशी दिखी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की 'सिफारिश एवं सलाह' से बंधे हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि 1993 में दिल्ली को सरकार बनाने का अधिकार मिला लेकिन दिल्ली की लोकतांत्रित रूप से निर्वाचित सरकार को 2018 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पूर्ण अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था...2018 दिल्ली के इतिहास में एक 'ऐतिहासिक वर्ष' के तौर पर पहचाना जाएगा।' इस वर्ष घर तक राशन पहुंचाना, शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित आप सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाएं भी पारित हुईं। सिसोदिया ने इसपर शोक जताया कि सेवाओं के दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण 'आप' नई नौकरियों का सृजन नहीं कर पाई।

'नेहरू गोवध पर प्रतिबंध का विषय राज्यों पर छोड़ने के पक्षधर थे'

● राज्यों को अपने यहां गोवध पर प्रतिबंध लगाने की पूरी आजादी है, लेकिन इस मुद्दे पर पूरे देश में एक समान नीति बना देना बेतुकी बात होगी

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। गोरक्षा के मुद्दे पर देश में राजनीतिक बहस जारी है लेकिन आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करीब 66 वर्ष पहले कहा था कि राज्यों को अपने यहां गोवध पर प्रतिबंध लगाने की पूरी आजादी है, लेकिन इस मुद्दे पर पूरे देश में एक समान नीति बना देना बेतुकी बात होगी। नेहरू ने 29 नवंबर 1952 को मध्य प्रदेश के भेलसा (अब विदिशा) में एक जनसभा में यह बात कही थी। पत्रकार पीयूष बबेले द्वारा लिखी संवाद प्रकाशन की पुस्तक 'नेहरूः मिथक और सत्य' में गोरक्षा के विविध आयामों पर पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचारों को उनके भाषणों एवं पत्रों के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष ने गोरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। आरएसए ने 26 अक्टूबर 1952 से देश में गोवध के खिलाफ अभियान चलाया और केंद्र सरकार से गोवध पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने की मांग की गई। पुस्तक के अनुसार, इन घटनाक्रमों के मद्देनजर 31 अक्टूबर 1952 को नागपुर में एक जनसभा में नेहरू ने कहा, 'आरएसएस का गोहत्या के खिलाफ अभियान एक सियासी चाल है। अभियान का गाय से कोई लेना-देना नहीं है।

अभियान से वह लोग जुड़े हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में कामयाब नहीं हो सके। मैं इसके उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ने को तरजीह दूंगा। राज्य सरकारें अपनी स्थानीय जरूरतों के लिहाज से इस पर फैसला लें।

सुधार उपायों को क्रियान्वयन पर होगा नीति आयोग का जोर

देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले साल रहेगी करीब 7.8 प्रतिशत

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि आयोग की नये साल में आर्थिक वृद्धि को गति देने, इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा मोदी सरकार के सुधार कार्यक्रमों को तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये संबंधित उपायों पर जोर देने की योजना है। कुमार ने समाचार एजेंसी से कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले साल करीब 7.8 प्रतिशत रहेगी और निवेश चक्र में अब तेजी आ रही है तथा इसमें आने वाले समय में और मजबूती आएगी। हमें कुछ और निजी निवेश देखने को मिलेंगे। देश की आर्थिक वृद्धि दर मार्च 2018 में समाप्त वित्त वर्ष में 6.7 प्रतिशत रही थी। कुमार ने कहा कि मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि नकदी की समस्या से जूझ रहे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र का भी मसला दूर होगा और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत आने वाले बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी...इन चीजों से निवेश चक्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई सुधारों को आगे बढ़ाया है और उच्च वृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति की नींव तैयार की है। अब समय उसके क्रियान्वयन पर जोर देने का है। कुमार ने कहा कि मुझे भरोसा है कि इलेक्ट्रानिक वाहन, ऊर्जा क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये कुछ और नीतिगत सुधारों की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पहली बार आप कम महंगाई दर के साथ 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। यह मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद को बताता है। यह 2022-23 तक 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने का आधार है। आयोग ने 2018 में आर्थिक वृद्धि दर में संशोधन को लेकर निशाने पर रहा। इस संशोधन के कारण पूर्व संप्रग शासन में वृद्धि दर पहले के अनुमान के मुकाबले घट गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पिछले महीने 2004-05 के बजाए नये आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग करते हुए आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़ों को संशोधित किया था। इससे पूर्व कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर पूर्व के अनुमान के मुकाबले घट गयी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम समेत अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी के आंकड़ों में संशोधन में नीति आयोग के शामिल होने पर सवाल उठाये और संदेह दूर करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की मांग की।

दिल्ली में पड़ती 'बर्फ' का विडियो वायरल

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। शनिवार को एक विडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें शख्स 'दिल्ली शिमला बन गई है, दिल्ली श्रीनगर जैसी हो गई है' चिल्ला रहा है। पश्चिम विहार के इस विडियो में शख्स कार की छत से कुछ सफेद-सफेद उठा रहा था, जिसको वह बर्फ बताता है। इसके बाद से लोगों को लगने लगा कि सच में दिल्ली में भी बर्फ पड़ने लगी है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मौसम विभाग (आईएमडी) के रीजनल हेड बीपी यादव ने भी उस विडियो को देखा। वह बताते हैं कि जो सफेद चीज दिख रही है वह असल में बर्फ नहीं है बल्कि फ्रॉस्ट है। बता दें कि शनिवार को तापमान 2.6 डिग्री तक गिर गया था, यह सीजन का सबसे ठंडा दिन था। इसकी वजह से फ्रॉस्ट जमना बिल्कुल आम बात है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह वाष्पीकरण की वजह से हुई ठंडक और ग्लास और मेटल के हीट न सह पाने के चलते होता है। फिर जैसे-जैसे तापमान गिरता है, कार की गर्माहट ट्रांसडक्शन की वजह से कम हो जाती है। फिर कार का बिल्कुल समतल सरफेस भी फ्रॉस्ट के बनने में मदद करता है। ठंड बढ़ने के साथ-साथ फ्रॉस्ट के कुछ और मामले भी देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग पहले ही हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि में शीत लहर से संबंधित रेड अलर्ट जारी कर चुका है।